



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4029]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 11, 2018/आश्विन 19, 1940

No. 4029]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 11, 2018/ASVINA 19, 1940

## उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2018

**का.आ. 5219(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने इथेनोल का उत्पादन बढ़ाने और विशेष रूप से अधिशेष वाले मौसम में पेट्रोल के साथ इथेनोल ब्लेंडिंग (ईबीपी) कार्यक्रम के अधीन इसकी आपूर्ति बढ़ाने और इससे चीनी मिलों की नकदी की स्थिति में सुधार करने, ताकि उन्हें किसानों के गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने में सक्षम बनाया जा सके, की दृष्टि से अधिसूचना सं. का.आ. 3523(अ), दिनांक 19.07.2018 द्वारा एक स्कीम अर्थात्—‘इथेनोल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उसमें वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम’ अधिसूचित की थी, जिसे तत्पश्चात अधिसूचना सं. का.आ. 3952(अ), दिनांक 09.08.2018 द्वारा संशोधित किया गया था।

2. दिनांक 19.07.2018 की उक्त अधिसूचना के पैरा 9 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार अब उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित परिवर्तन करती है:-

(क) पैरा 3 (i) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा:

“बैंकों/राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा दिए गए क्रृष्ण पर बैंकों/राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा प्रभारित 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज छूट अथवा ब्याज दर की 50 प्रतिशत राशि, जो भी कम हो, केन्द्रीय सरकार द्वारा पांच वर्ष के लिए वहन की जाएगी।”

(ख) पैरा 5 (i) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा:

“आवेदन-सह-प्रस्ताव की जांच के बाद खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग अपना सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करेगा और ऐसे अनुमोदित प्रस्ताव क्रृष्ण देने वाले बैंकों/राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को क्रृष्ण की स्वीकृति हेतु विचारार्थ संस्तुत करेगा। बैंकों/राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को अपने वाणिज्यिक मानदंडों/नीतियों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित पुनः संरचना दिशा-निर्देशों सहित विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुपालन में क्रृष्ण स्वीकृत/निर्गत करने की स्वतन्त्रता होगी।”

(ग) पैरा 5 (v) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा:

“वित्तीय सेवाएं विभाग इस स्कीम को प्रचालित करने के लिए नोडल बैंक के रूप में नाबांड की नियुक्ति सहित बैंकों/राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को समुचित अनुदेश जारी करेगा।”

(घ) पैरा 6(iii) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा:

“चीनी मिलों के पास अधिशेष नकद प्रवाह की स्थिति में भुगतान में तेजी लाने का निर्णय बैंकों/राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा लिया जाएगा और ऋण खाते पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की ब्याज छूट संबंधी देयता तदनुसार कम हो जाएगी।”

[फा. सं. 1(10)/2018-एसपी-1]

सुरेश कुमार वशिष्ठ, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

### (Department of Food and Public Distribution)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2018

**S.O. 5219(E).**—Whereas the Central Government, with a view to increase production of ethanol and its supply under Ethanol Blended with Petrol (EBP) Programme, especially in the surplus seasons and thereby to improve the liquidity position of the sugar mills enabling them to clear cane price arrears of the farmers, has notified the scheme namely “Scheme for extending financial assistance to sugar mills for enhancement and augmentation of ethanol production capacity” vide notification No. S.O. 3523(E), dated 19.07.2018, which was subsequently amended *vide* notification No. S.O. 3952(E), dated 09.08.2018.

2. Now in pursuance of para 9 of the said notification dated 19.07.2018, Central Government makes following changes in the said notification:—

(a) Para 3(i) would be substituted by the following:—

“Interest subvention @ 6% per annum or 50% of rate of interest charged by banks/National Cooperative Development Corporation (NCDC), whichever is lower, on the loans to be extended by banks/NCDC, shall be borne by the Central Government for five years”

(b) Para 5(i) would be substituted by the following:—

“After scrutinizing the applications cum proposals, DFPD will accord it's in principle approval and recommend such approved proposals to the lending banks/NCDC for considering sanction of loan. Banks / NCDC would be at liberty to sanction/release the loan as per their commercial norms/policies and in compliance with regulatory guidelines, including the restructuring guidelines, as notified by RBI from time to time.”

(c) Para 5(v) would be substituted by the following:—

“The Department of Financial Services (DFS) will issue suitable instructions to the banks/NCDC to operationalize the scheme including appointment of NABARD as a nodal bank”.

(d) Para 6(iii) would be substituted by the following:—

“In the event of surplus cash flow with the sugar mills, accelerated payments may be decided by the banks/NCDC and the interest subvention liability of DFPD towards loan account would accordingly get reduced.”

[F. No. 1(10)/2018-SP-I]

SURESH KUMAR VASHISHTH, Jt. Secy.